भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2127
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

ई-शिक्षा

2127. श्री अरुण गोविल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेरठ सहित पूरे देश में सभी को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रमों की घोषणा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या छात्र और शिक्षक ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट और वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विभिन्न स्थानों से एक साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं;
(घ) क्या सरकार का विचार स्कूलों में इस तरह के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का है;
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश भर में, उन स्कूलों का राज्य-वार विशेषकर मेरठ में ब्यौरा क्या है, जिनमें वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 के पैरा 24.4 (ग) में ऑनलाइन शिक्षण मंच और साधन उपकरण जैसी विभिन्न प्रमुख पहलों पर जोर दिया गया है: स्वयं, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए संरचित, उपयोगकर्ता के अनुकूल, समृद्ध सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि वर्तमान महामारी ने दिखाया है, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए टू-वे वीडियो और टू-वे-ऑडियो इंटरफ़ेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता हैं।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न पहलें की हैं जिनमें ई-लर्निंग कार्यक्रम शामिल हैं। ये पहल देश भर के सभी शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

1) पीएम ई-विद्या: पीएम ई-विद्या डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा सहित ई-शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम किया जा सके। पीएम ई-विद्या से देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चे लाभान्वित होते हैं।

पीएम ई-विद्या के अंतर्गत प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- दीक्षा पोर्टल - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-लर्निंग सामग्री और सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) प्रदान करने के लिए राष्ट्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा।
- डीटीएच टीवी चैनल - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चैनल आवंटित किया गया है और वे इसका उपयोग कर रहे हैं।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।
- दृष्टि एवं श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली सुगम्य सूचना प्रणाली (डेजी) और सांकेतिक भाषा पर विशेष ई-सामग्री विकसित की गई है। यह एनआईओएस की वेबसाइट/यूट्यूब पर उपलब्ध है।

2) शिक्षा मंत्रालय निष्ठा- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी कार्यान्वित कर रहा है।

प्रारंभिक, माध्यमिक, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के लिए निष्ठा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। निष्ठा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर रूप से बनाए गए ई-कंटेंट का उपयोग करके ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। 65 लाख से अधिक शिक्षकों ने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें से 45 लाख से अधिक ने ई-लर्निंग मोड में पूरा किया है।

3) आईसीटी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) देश भर के सभी उच्चतर शिक्षा छात्रों के लिए बहु-मॉडल दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई-शिक्षा तक किसी भी समय, कहीं भी पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे आईआईटी-मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईएम-बेंगलुरु, इग्नू और कई अन्य जैसे शीर्ष संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के 'आईसीटी और डिजिटल पहल' घटक में कक्षा VI से XII वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं, जो बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन हैं। "आईसीटी लैब" और "स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम" के विकल्पों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के मानदंडों में आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों घटकों की खरीद के लिए सहायकता शामिल है, जैसे डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षाएं, वर्चुअल कक्षाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, दीक्षा के अनुरूप ओपन-सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर (एफओएसएस), इंटरनेट कनेक्टिविटी, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि जो ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट और वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विभिन्न स्थानों से शिक्षकों, छात्रों और अन्य लोगों के बीच एक साथ बातचीत को सक्षम बनाता है। इस योजना के मानदंड https://samagra.education.gov.in/docs/ss_implementation.pdf पर देखे जा सकते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजना/परियोजना/पहल के अंतर्गत कवर किए गए स्कूलों की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मेरठ जिले में 141 स्मार्ट-क्लासेस और 14 आईसीटी लैब स्थापित किए गए हैं।

अनुलग्नक

ई-शिक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अरुण गोविल द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2127 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईसीटी प्रयोगशाला अनुमोदन (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक)	स्मार्ट क्लासरूम अनुमोदन (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	0
आंध्र प्रदेश	2687	5190
अरुणाचल प्रदेश	291	243
असम	3132	6416
बिहार	0	4846
चंडीगढ़	35	186
छत्तीसगढ़	1734	10318
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	98	190
दिल्ली	7	1119
गोवा	3	24
गुजरात	728	7078
हरियाणा	620	3520
हिमाचल प्रदेश	995	2248
जम्मू और कश्मीर	1512	3338
झारखंड	3859	1270
कर्नाटक	1123	1868
केरल	0	509
लद्दाख	119	123
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	1801	7934
महाराष्ट्र	637	3501
मणिपुर	272	544
मेघालय	267	25
मिजोरम	651	238
नागालैंड	0	690
ओडिशा	302	7336
पुडुचेरी	16	145
पंजाब	1881	3885

राजस्थान	2988	12627
सिक्किम	99	301
तमिलनाडु	9115	7044
तेलंगाना	1086	3982
त्रिपुरा	773	886
उत्तर प्रदेश	5565	26746
उत्तराखंड	240	2511
पश्चिम बंगाल	1361	0
कुल	44025	126881

स्रोत: प्रबंध

*****